[Shri Madhavrao Scindia]

(iv) Intelligence about gang movement has fallen into disarray because of the confusion following the surrenders.

(v) Everytime dacoity has reappeared in Madhya Pradesh, it has become necessary to organise village resistance squads on the right lines. It may be necessary to increase the number of fire-arms in selected villages and to train and develop a spirit of confidence in the villages. A good team of officers would be required for this purpose. They should primarily be picked from the police and from well-motivated persons of the area.

(vi) The BSF should be used to combat this problem but the deployment should be of at least 2000 men.

States like Madhya Pradesh have the capacity to deal with the dacoity problem with zeal, initiative and courage. They have never lacked resources. If the resources question is tackled it should be possible to make an improvement in the dacoity situation.

(ii) Drinking Water Problem in Government Quarters in Gole Market Area, New Delhi.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, संसद भवन से 1 मील से भी कम की दूरी पर गोल मार्केट का क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में केन्द्रीय कर्मचारी निवास करते हैं। कर्मचारियों को जीवन की बुनियादी सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। पेय जल की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय आवास तथा निर्माण विभाग सीधा उत्तरदायी है।

यह बड़े खेद का विषय है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए पेय जल की कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। मकानों के निर्माण के साथ साथ पीने के पानी का प्रबन्ध जरूरी था, किन्तु अनेक ऊपरी मंजिलों में पानी नहीं, पहुंच पाता। मैंने स्वयं महिलाओं को नीचे से पानी भर कर चौथी मंजिल तक ले जाते हुए देखा है। यदि सर्दी के मौसम में यह हाल है, तो गर्मी में इन परिवारों की क्या दशा होगी, इसका अनुमान लगाना किसी निष्ठुर हृदय के लिए भी असम्भव नहीं होना चाहिए।

जहां पानी मिलता है, वहां क्या दुर्दशा है, इसका उदाहरण 15 फरवरी, 1981 को सामने आया, जब गोल मार्केट के सेक्टर "सी" में, जहां 340 क्वार्टर बने हुए हैं, ब्लाक नं० 2 में सवेरे 7 बजे पानी बन्द हो गया। जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि 1 से 4 तक सभी टैंक सूखे पड़े हैं। काफी दौड़-धूप के बाद निर्माण विभाग को सक्रिय किया जा सका। किन्तु कर्मचारी यह देख कर दंग रह गये कि टैंकों में मरे हुए गिरगिट पड़े थे और काफी मोटी कीचड़ जमी हुई थी। नियम के अनुसार टैंकों की निश्चित समय पर सफाई होनी चाहिए। स्पष्टतः प्रशासन इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का पालन करने में विफल रहा है। पीने के पानी के टैंकों में गिरगिटों का सड़ जाना लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कर्मचारी और उनके परिवार, जिनमें बच्चे शामिल हैं, कीचड़ से भरा हुआ पानी पीते हैं, यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए।

मेरी मांग है कि 15 फरवरी को गोल मार्केट के सैक्टर सी में पीने के पानी की आपूर्ति क्यों नहीं की गई, इसकी जांच की जाये। यह भी पता लगाया जाये कि पानी के टैंकों में गिरगिटों के गिरने और कीचड़ के जमा होने के लिए कौन जिम्मेदार है।

(iii) Increase in the Cement Quota for West Bengal

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Sir, a multipurpose stadium of international standards is now being built at the

salt Lake City of Calcutta. The Cement Controller informed the West Bengal Government of his inability to make any *ad hoc* allocation of cement for the construction of the stadium.

The quota allotted by the Central Government is too inadequate to meet even the urgent developmental needs of the State. Unless the quota of allotment of cement is increased, it will not be possible for the State Government to complete the stadium.

I, therefore, urge upon the Government to increase the cement quota of West Bengal.

(iv) ENLISTING OF TRIBALS IN THE CURRENT CENSUS OPERATIONS.

SHRI PIUS TIRKEY (Alipurduar): It is a matter of great regret that there is no uniformity in enlisting the tribals in the list of Scheduled Tribes in different States of India. The tribals are national assets and tribalism is a national issue. But, at present, tribals are not being recognised at the national level. The Scheduled Tribes residing in the Union Territories of Delhi, Andaman and Nicobar etc. and in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh etc. are being debarred from their rights of being tribals. The present census operation in the midst of this uncertainly of the principles of tribalism would be *ultra vires* and unconstitutional.

In many parts of India, for example, Bombay, Delhi, Gujarat, Haryana, Punjab and Assam, the census operation is vehemently being opposed. Tribalism has become a new property of the persons belonging to Scheduled Tribe community. The tribal people inheriting this property in certain States shall never lose it in another State. If this property is snatched in any State, or in Union Territories, then this will amount to a robbery or a dacoity. In the midst of this uncertainty, the denial of this valuable property and personal right of the tribal people living in parts of the country would be an injustice to the tribal people by the respective State Governments and Union Territories. The Home Minister and the Law Minister should immediately clarify the position.

Therefore, I submit that a Parliamentary Committee for revision of the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes may please be formed early.

(v) NEED TO STOP CONSTRUCTION OF DAM IN GHAZIPUR DISTRICT OF UTTAR PRADESH.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गाजीपुर बलिया मार्ग पर गौसपुर से बलिया बैरिया बांध तक बाढ़ की रोकथाम के लिए एक बांध बनाए जाने की कार्यवाही चल रही है। उक्त कार्यवाही से बाढ़ की रोकथाम तो नहीं हो पाएगी लेकिन गाजीपुर बलिया मार्ग और गंगा नदी के बीच में स्थित गांवों को बाढ़ के समय जबर्दस्त खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह गांव बुरी तरह पानी में डूब जाएंगे। कच्चे बांध के टूटने की स्थिति में सड़क के दूसरी तरफ के गांव भी पानी की तेज धारा के प्रवाह में विलीन हो जाएंगे।

एक खतरा यह भी है कि भमई नदी का पानी जो उस क्षेत्र में बरसात के जमाने में फैल जाता है उसे भी निकालने में कठिनाई होगी और उक्त क्षेत्र के बहुत सारे भाग हमेशा पानी में डूबे रहेंगे।